



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ष-2

16 फरवरी, 1933 (श०)
 मंगलवार, तिथि

06 मार्च, 2012 (ई०)
 प्रश्नों की कुल संख्या—02

(1) शिक्षा विभाग

.. .. .

02

कुल पृष्ठ

02

शिक्षित करना

'क'-11. श्री अवनीश कुमार सिंह—स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 24 जुलाई, 2011 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "निरक्षरों को साक्षर बनाने में नहीं लगता राज्यों का मन" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा (प्रा०शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009-10 में प्रौढ़ अनपढ़ों को शिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा "साक्षर भारत मिशन" शुरू किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सहमति जताने तथा दो वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य में सभी जिला एवं प्रखण्डों पर समन्वयक नियुक्त नहीं किये गये हैं, जिसके कारण "साक्षर भारत मिशन" प्रदेश में विफल हो गया और एक भी अशिक्षित प्रौढ़ शिक्षित नहीं हो पाये;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपरोक्त योजना की विफलता के लिए कौन दोषी है तथा प्रौढ़ों को शिक्षित करने की योजना सरकार कबतक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वर्ष 2009-10 के सितम्बर माह में केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के भोजपुर, बेगूसराय एवं खगड़िया जिले के लिये साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी एवं मार्च, 2010 से बिहार के उक्त जिलों में यह कार्यक्रम लागू किया गया।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के सितम्बर माह में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों (अखिल छोड़कर) में साक्षर भारत कार्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी गयी तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के सितम्बर में अखिल जिले में भी उक्त कार्यक्रम संचालन का आदेश प्राप्त हो गया। सभी जिलों एवं प्रखण्डों में समन्वयकों का चयन कर लिया गया है एवं कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

(3) वयस्कों को साक्षर करने की योजना कार्यरत है।

दोषी पर कार्रवाई

33. डॉ० अच्युतानन्द—साप्ताहिक पत्रिका के दिनांक 27 जनवरी, 2012 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "स्कूलों में साढ़े तीन लाख फर्जी नामांकन" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा (मा०शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की जाँच एजेंसी बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन के द्वारा कराए गए 12 जिलों के सर्वे में राज्य के साढ़े तीन लाख बच्चों का नामांकन दो-दो स्कूलों में पाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 28 जिलों में सर्वे कराना अभी बाकी है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त फर्जी नामांकन के कारण मध्याह्न भोजन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री साईफिल योजना की राशि में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी हुई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी स्कूलों में फर्जी नामांकन की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 6 मार्च, 2012 (ई०)।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

नोट—'क'-दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सदन द्वारा स्वीकृत।